



आलोचकों को करारा जवाब

Page-04



सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा पहली बार साथ स्पॉट

Page-0



समर्थकों का धन्यवाद, कहा – संघर्ष अभी जारी रहेगा

राजनीतिक साजिश का आरोप, विरोधियों पर साधा निशाना

दिल्ली की स्थानीय कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिंसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट के ऑर्डर मिलने बाद उन्होंने मीडिया और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है. इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से लेकर ED और CBI जैसी सरकारी एजेंसियों पर जमकर तंज कसे. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पूरा षड्यंत्र प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने रचा, उन दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए. जिन्होंने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया मैं उनका धन्यवाद करता हूं. आप जानते हैं कि किस तरह पिछले 4 साल से, ईडी, सीबीआई और सारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर शराबा घोटाला नामक एक आरोप लगाया गया. सीबीआई और ईडी ने उसमें चार्जशीट दाखिल की. आज कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा भी चलाया जा सके. कोर्ट का कहना है कि इतना गलत, फर्जी केस है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश रचकर देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिंसोदिया और आम आदमी पार्टी (AAP) को बदनाम करने की कोशिश की



शुभांशु शुक्ला का ऐतिहासिक अंतरिक्ष सफर



जब हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूछा था राकेश शर्मा जी से जो पहले भारत के अंतरिक्ष यात्री थे कि वहां से भारत कैसा दिखता है? तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 25 जून 2025 की दोपहर जैसे ही घड़ी में 12:01 का वक्त दिखाया भारत का दिल एक साथ धड़क उठा अमेरिका के कनेडी स्पेस सेंटर से जैसे ही फाल्कन रॉकेट से बंधा स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आसमान की ऊंचाइयों की ओर बढ़ा। उसमें सवार एक भारतीय का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वो नाम है शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद 41 साल तक भारत ने इंतजार किया था। उस पल का जब कोई भारतीय दोबारा अंतरिक्ष की दहलीज पर कदम रखेगा और इस इंतजार को तोड़ा लखनऊ के लाल भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने।

‘कृषि प्रधान से जाति प्रधान हो गया देश’ – राजभर

खतौली तहसील क्षेत्र में वंचित शोषित एकता टैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने मुजफ्फरनगर दंगों की याद ताजा करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा(OP Rajbhar Bayan). इसको लेकर उन्होंने कहा कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, कत्लेआम हो रहा था, तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और सैफई में बैठकर नाच देख रहे थे. मुख्यमंत्री का काम होता है कि जिस जिले में हालात खराब हैं, पहले उसे सुधारे, लेकिन उनके लिए नाच सर्वोपरि था. यहां लोग मारे जा रहे थे, गांव से पलायन कर रहे थे और भाग रहे थे, जबकि बाप-बेटे वहां बैठे नाच देख रहे थे.

पाकिस्तान-तालिबान संबंधों में दरार की जड़ क्या?



पाकिस्तान ने कथित तौर पर दावा किया है कि उसके नए मिलिट्री हमले में 274 अफ़गान तालिबान लड़ाके मारे गए और कई घायल हुए हैं। काबुल को तनाव बढ़ने की चेतावनी देते हुए, इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि सेना में “किसी भी आक्रामक इरादे को कुचलने” की क्षमता है, जबकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ़ ने कहा कि हमारे सब्र की हद हो गई है और चेतावनी दी कि अब दोनों पक्षों के बीच खुली जंग है। न्यूज़ एजेंसी एएफपी के पत्रकारों ने तोरख़म बॉर्डर क्रॉसिंग के पास नई गोलीबारी और गोलाबारी की ख़बर दी। शुक्रवार को सुबह करीब 9:30 बजे से अफ़ग़ानिस्तान की तरफ से गोलाबारी की आवाज़ें सुनी गईं, जिसके बाद बॉर्डर पार से गोलीबारी हुई। पाकिस्तान के डॉन ने सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी

एयर फ़ोर्स (PAF) के जेट अफ़ग़ानिस्तान के कंधार इलाके के आसमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टर ने सिक्वोरिटी सूत्रों के हवाले से कहा, “पाकिस्तानी आर्म्ड फ़ोर्स किसी भी हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उनके पास करारा जवाब देने की काबिलियत है। दोनों पक्षों ने जो हुआ उसके बारे में बिल्कुल अलग-अलग बातें बताई हैं। तालिबान सरकार ने शुक्रवार के एयर स्ट्राइक की पुष्टि की, प्रक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफ़ग़ान सेना ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जबकि अफ़ग़ान सैनिकों में मरने वालों की संख्या 13 बताई। पाकिस्तानी सेना के पब्लिसिटी विंग, I S P R के हेड, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी ने रिपोर्टों को बताया कि “तालिबान सरकार के 274 सदस्य और आतंकवादी” मारे गए हैं, जबकि 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। दोनों पक्षों के हताहत होने के दावों को अलग-

अलग वेरिफ़ाई करना मुश्किल है। तालिबान ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि उसने रात भर चले ऑपरेशन में कम से कम 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। अफ़ग़ान सरकार ने दो पाकिस्तानी आर्मी बेस पर कब्ज़ा करने का भी दावा किया। तालिबान के एक बयान में कहा गया, कुल 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, दो बेस और 19 पोस्ट पर कब्ज़ा कर लिया गया। इन हमलों में ड्रैड लाइन पर, पत्तिका, पक्तिया, खोस्त, नंगरहार, कुनार और नूरिस्तान प्रांतों के पास पाकिस्तानी मिलिट्री फ़ोर्स को निशाना बनाया गया। प्लान के मुताबिक पूरे हुए, और आधी रात को इस्लामिक अमीरात के चीफ ऑफ़ जनरल स्टाफ़ के आदेश पर, लड़ाई बंद हो गई। पाकिस्तान ने कहा है कि उसके सुरक्षा बलों ने ख़ैबर पख़्तूनख्वा के एबटाबाद में एक ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है, डॉन ने जिला पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया।

राजस्थान में सीएम भजनलाल का बड़ा एक्शन, माउंट आबू समेत 3 शहरों के नाम बदल गए



मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकप्रिय हिल स्टेशन माउंट आबू को अब आबू राज के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जहाजपुर को अब यज्ञपुर कहा जाएगा, और कामा का नाम बदलकर कामवन कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में घोषणा की कि राज्य के तीन शहरों के नाम बदले जाएंगे। इस घोषणा ने लोगों का ध्यान खींचा है क्योंकि इसमें जाने-माने शहर और कस्बे शामिल हैं। सत्र के दौरान जानकारी देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकप्रिय हिल स्टेशन माउंट आबू को अब आबू राज के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जहाजपुर को अब यज्ञपुर कहा जाएगा, और कामा का नाम बदलकर कामवन कर दिया गया है।

तमिलनाडु-पुडुचेरी को 7,100 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करने वाले हैं। राजस्थान और गुजरात के अपने दौरे के बाद, प्रधानमंत्री 28 फरवरी को रात करीब 9 बजे चेन्नई पहुंचेंगे। सोमवार सुबह करीब 11:45 बजे, प्रधानमंत्री पुडुचेरी में 2,700 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, शिलान्यास और देश को समर्पित करेंगे। इस इवेंट के दौरान वे एक पब्लिक गैदरिंग को भी एड्रेस करेंगे। एक ऑफिशियल रिलीज़ के मुताबिक, इन प्रोजेक्ट्स का मकसद पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी सर्विसेज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थकेयर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मज़बूत करना है। PM ई-बस

सेवा इनिशिएटिव के तहत, वे नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। वे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, CIIIS स्क्रीम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज़ और कई सीवरेज और वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कराईकल में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ब्लॉक और गंगा हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे। वे JIPMER में मॉडर्न रीजनल कैंसर सेंटर और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में नई बिल्डिंग्स का भी उद्घाटन करेंगे। इस दिन की एक खास बात 750 एकड़ के करासुर-सेदारापेट इंडस्ट्रियल एस्टेट को देश को



समर्पित करना होगा। इस एस्टेट में एक फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, IT पार्क, IT मद्रास का एक रिसर्च सेंटर और JIPMER की एडवांस्ड हेल्थकेयर सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री पीने के पानी के अपग्रेड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 41

ग्रामीण सड़कों के निर्माण, हेरिटेज टाउन डेवलपमेंट, MISHTI स्क्रीम के तहत मैंग्रोव रेस्टोरेशन, और पानी, सफाई और बिजली के खास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिवर्सल सीरिएक ऑर्थोडॉक्स चर्च के सर्वोच्च प्रमुख से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल सीरिएक ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख हिज होलीनेस मोरन मोर इग्नेशियस एफ्रेम II से मुलाकात की। दोनों ने धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री और चर्च प्रमुख ने समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय और समावेशिता को महत्व दिया।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में 'एंटीओक और ऑल द ईस्ट' के पैट्रिआर्क तथा यूनिवर्सल सीरिएक ऑर्थोडॉक्स चर्च के सर्वोच्च प्रमुख 'हिज होलीनेस मोरन मोर इग्नेशियस एफ्रेम द्वितीय' से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक रही। यह मुलाकात धार्मिक और सामाजिक संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विशेष अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि 'हिज होलीनेस मोरन मोर इग्नेशियस



एफ्रेम द्वितीय' से मिलकर वे स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि उनके बीच कई अहम मुद्दों पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा हुई। वहीं, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद 'हिज होलीनेस' ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने इस भेंट को अत्यंत सार्थक और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि भारत जैसे महान राष्ट्र की मूल भावना समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए न्याय

सुनिश्चित करने की रही है। इस मुलाकात को भारत की विविध धार्मिक परंपराओं और अंतरराष्ट्रीय धार्मिक नेतृत्व के साथ संवाद को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूनिवर्सल सीरिएक ऑर्थोडॉक्स चर्च विश्व के प्राचीन ईसाई समुदायों में से एक है और उसका वैश्विक स्तर पर व्यापक अनुयायी वर्ग है। ऐसे में इस भेंट को धार्मिक सौहार्द, पारस्परिक सम्मान और संवाद को बढ़ावा देने की दिशा में सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार

की मुलाकातें भारत की बहुलतावादी परंपरा और समावेशी दृष्टिकोण को रेखांकित करती हैं। यह संवाद न केवल धार्मिक समुदायों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ाता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को भी सुदृढ़ करता है। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 'हिज होलीनेस मोरन मोर इग्नेशियस एफ्रेम द्वितीय' की यह मुलाकात आपसी सम्मान, संवाद और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा रही है।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर



टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी शुक्रवार को मुंबई पहुंचे। वे 2 मार्च तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। यह कार्नी का भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को पुनर्स्थापित करना और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना है। कनाडा फिलहाल अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है और भारत, चीन तथा मध्य पूर्व के देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। एएफपी के अनुसार, मुंबई पहुंचने के बाद कार्नी नई दिल्ली खाना होने से पहले उद्योग जगत के नेताओं से मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली में सोमवार को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात प्रस्तावित है। हाल के वर्षों में भारत और कनाडा के संबंध उस समय तनावपूर्ण हो गए थे, जब पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया था। नई दिल्ली ने इन आरोपों को बार-बार खारिज किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्नी अपने पूर्ववर्ती के विपरीत पंजाब का दौरा नहीं करेंगे, जिसे सिख अलगाववादी राजनीति से जुड़ा क्षेत्र माना जाता है। व्यापारिक समुदाय ने इस यात्रा को प्रतीकात्मकता से अधिक प्रत्यक्ष व्यापार और निवेश पर केंद्रित बताया है। यह दौरा भारत और यूरोपीय संघ के बीच हालिया व्यापार समझौते के बाद हो रहा है, जिससे कनाडा के साथ भी समान समझौते की संभावनाएं बढ़ी हैं। रिपोर्टों के अनुसार, वार्ता में दीर्घकालिक यूरनियम आपूर्ति समझौता तथा ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हो सकती है।

ईरान में प्रदर्शनों के दौरान अस्पतालों में सुरक्षा बलों की दखलअंदाजी के आरोप

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

ईरान में पिछले महीने सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर कार्रवाई के दौरान अस्पतालों में सुरक्षा बलों की कथित दखलअंदाजी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार, कई शहरों में घायल प्रदर्शनकारियों के इलाज के दौरान सादे कपड़ों में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी अस्पतालों में पहुंच गए और चिकित्सा प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। उत्तरी शहर रश्त के एक डॉक्टर ने एपी को बताया कि करीब 40 वर्षीय एक व्यक्ति को सिर में नजदीक से गोली लगने के बाद अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन तभी सुरक्षाकर्मी वहां पहुंच गए और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। कुछ मिनट बाद मरीज की मौत हो गई और सुरक्षाकर्मी उसका शव अन्य शवों के साथ ले गए। रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी की शुरुआत में कई शहरों में इसी तरह की घटनाएं हुईं। प्रदर्शन 47 वर्ष पुराने इस्लामी गणराज्य के खिलाफ थे, जिनमें हजारों लोग घायल हुए। आरोप है कि सुरक्षाकर्मी अस्पतालों में इलाज की गिरानी करते थे, कई बार उपचार रोकते थे और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते थे। दर्जनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी की भी बात सामने आई है। यह जांच ईरान के तीन डॉक्टरों



और विदेश में रह रहे छह ईरानी चिकित्सा विशेषज्ञों से बातचीत, मानवाधिकार समूहों की रिपोर्ट और सोशल मीडिया वीडियो के विश्लेषण पर आधारित है। बर्लिन स्थित संगठन स्मृति सहायक ओस्लो स्थित ईरान मानवाधिकार केंद्र ने भी अस्पतालों के भीतर उपचार रोकने और मरीजों को वेंटिलेटर से हटाने जैसे आरोप दर्ज किए हैं। अमेरिका स्थित ईरानी इंटरनेशनल फिजीशियंस एसोसिएशन के अनुसार, गोरगान में एक अस्पताल की छत पर स्नाइपर तैनात थे। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अस्पतालों का इस स्तर पर सैन्यीकरण अभूतपूर्व है और इसे व्यवस्थित पैटर्न के रूप में देखा जा रहा है।



अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए तैयार किया 'स्कॉर्पियन स्ट्राइक' ड्रोन यूनिट

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण जंग, सीमा पर दोनों ओर से बड़े हमले

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भीषण जंग शुरू हो गई है। दोनों ओर की सेनाएं एक-दूसरे पर बड़े पैमाने पर हमले कर रही हैं। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर दबाव बना रहा था, लेकिन अफगानिस्तान ने अब जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अफगानिस्तान प्रशासन ने दावा किया है कि हालिया झड़पों में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। रैत शुरु हुई झड़पें देखते ही देखते युद्ध का रूप ले चुकी हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में कई स्थानों पर बमबारी की, जिसका अफगान सेनाओं ने मुहतोड़ जवाब दिया। अफगान फोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के जीएफ17 लड़ाकू विमान को मार गिराने का भी दावा किया है। तालिबान के हमलों के चलते पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हट गए। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल और कंधार में कुछ जगहों पर बमबारी की, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने इस कार्रवाई को पाकिस्तान की घुसपैठ और अफगान स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। तालिबान

के मिलिट्री ऑफ नेशन डिफेंस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी सीमाओं में खुलेआम घुसपैठ की और अफगान क्षेत्रों पर हमला किया। इसके जवाब में तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बड़े हमले किए। ड्रॉड लाइन पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हमलों के बाद यह जंग और भी तेज हो गई। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान भी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि "हमारे सन्न की इंतहा हो गई है, अब यहां खुली जंग है।" उन्होंने तालिबान अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बताने जैसी विवादित टिप्पणी भी की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह संघर्ष ड्रॉड लाइन के आसपास दोनों देशों की सेनाओं और एयरफोर्स के बीच जारी है। दोनों ओर बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें मिल रही हैं। यदि यह जंग तेज हुई, तो क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है। तालिबान और पाकिस्तानी सेना दोनों ही अपने हमलों और जवाबी कार्रवाइयों को जारी रखे हुए हैं, और अभी तक स्थिति नियंत्रण से बाहर प्रतीत हो रही है। संघर्ष के चलते स्थानीय नागरिकों में भी डर का माहौल है और इलाके में गंभीर सुरक्षा संकट उत्पन्न हो गया है।

चाबहार पोर्ट को लेकर भारत-ईरान रिश्तों में नई चुनौतियां

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

भारत और ईरान के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग का प्रमुख प्रतीक चाबहार पोर्ट हाल ही में विवादों के केंद्र में आ गया है। भारत और ईरान ने मिलकर इस पोर्ट का विकास किया है, जो हिंद महासागर क्षेत्र को मध्य एशिया और फिर यूरोप से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके माध्यम से भारत पाकिस्तान को बायपास कर ईरान और अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे उसे क्षेत्रीय रणनीतिक लाभ मिलता है। हालांकि, इस साल भारत ने अपने वित्तीय बजट में चाबहार परियोजना के लिए कोई फंड एलोकेशन नहीं किया, जिससे ईरान में निराशा की लहर दौड़ गई। ईरानी विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर कहा कि यह कदम दोनों देशों के लिए निराशाजनक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि चाबहार एक अत्यंत रणनीतिक बंदरगाह है और यदि इसका पूर्ण विकास किया जाए, तो यह भारत को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि वह एक दिन इस बंदरगाह के पूर्ण विकास को देखेंगे। उन्होंने भारत के साथ मजबूत और आत्मीय संबंधों की भी बात कही। इसके बावजूद, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को चाबहार पोर्ट परियोजना में आगे बढ़ने में चुनौतियां



का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और ईरान के संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों के चलते परियोजना की गति प्रभावित हो रही है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह कदम द्विपक्षीय संबंधों में अतिरिक्त जटिलता पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, चाबहार पोर्ट न केवल व्यापार और आर्थिक दृष्टि से, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से भी भारत और ईरान के लिए महत्वपूर्ण है। यदि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ता है और परियोजना को आवश्यक वित्तीय समर्थन

मिलता है, तो यह पोर्ट क्षेत्र में व्यापार और कनेक्टिविटी के नए अवसर खोल सकता है। हालांकि वर्तमान में बजट में फंड में अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते परियोजना की गति धीमी है, लेकिन दोनों देशों के बीच की दृगामी रणनीतिक साझेदारी इसे फिर से गति देने की संभावना रखती है। चाबहार पोर्ट भारत-ईरान संबंधों का प्रतीक है और इसके पूर्ण विकास को लेकर ईरान की उम्मीदें भारत से जुड़ी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत अपनी वित्तीय और नीतिगत प्रतिबद्धता मजबूत करता है, तो यह बंदरगाह दोनों देशों के लिए रणनीतिक और आर्थिक लाभ का मुख्य केंद्र बन सकता है।



संपादक की कलम से

आज के समय में लोकतंत्र और प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। विकास की गति तेज होना आवश्यक है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक संरचना प्रभावित न हो। देश के संवेदनशील सीमाई और जनसंख्या घनी क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी का महत्व विशेष होता है। ऐसे क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और सीमांत निगरानी के उपाय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सुरक्षा उपायों के कारण स्थानीय समाज और सामान्य नागरिकों के अधिकार प्रभावित न हों। सुरक्षा केवल राष्ट्रीय हित से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार और सामाजिक समरसता से भी जुड़ी है। किसी भी कदम को उठाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कानून के अनुरूप हो और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए न्यायपूर्ण भी हो। जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही समावेशी दृष्टिकोण भी बनाए रखना होगा। विकास और सुरक्षा का संतुलन केवल नीति बनाने से नहीं, बल्कि ठोस कदम, सतर्क प्रशासन, स्थानीय समुदायों के साथ संवाद और निगरानी से स्थापित होता है। सीमाई और संवेदनशील क्षेत्रों में न केवल सुरक्षा बलों की उपस्थिति, बल्कि नागरिकों को विश्वास दिलाना भी जरूरी है कि उनकी जरूरतों और सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी ओर, असामाजिक गतिविधियों और अपराध को रोकने के लिए जागरूकता, निगरानी और कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में लापरवाही या अव्यवस्था समाज में असुरक्षा और अविश्वास पैदा कर सकती है। इसलिए प्रशासन और नागरिक दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में जनता की भलाई और सुरक्षा सर्वोपरि होती है। नीति निर्धारक और प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी उपाय न्यायपूर्ण, पारदर्शी और संवेदनशील हों। केवल तभी समाज में स्थिरता, विकास और विश्वास के मजबूत स्तंभ कायम रह सकते हैं। विकास और सुरक्षा का संतुलन साधना आसान नहीं है, लेकिन यह हमारी लोकतांत्रिक परंपरा और नागरिक सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का हिस्सा है। यही वह रास्ता है, जो देश को स्थायी प्रगति, सामाजिक समरसता और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा।

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपी बरी कोर्ट ने कहा—साज़िश का कोई सबूत नहीं

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के. कविता समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि किसी भी अपराधिक साज़िश या गलत इरादे का ठोस सबूत नहीं है और CBI आरोप साबित करने में नाकाम रही।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तेलंगाना की एमएलसी के. कविता समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच किए गए इस बहुचर्चित मामले में अदालत ने स्पष्ट कहा कि एक्साइज पॉलिसी के निर्माण में किसी भी प्रकार की अपराधिक साज़िश या अवैध कृत्य का कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। अदालत ने पाया कि मामले में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि नीति निर्माण के दौरान कोई अपराधिक मंशा या सुनियोजित साज़िश थी। न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “एक्साइज पॉलिसी में कोई बड़ी साज़िश या अपराधिक इरादा नहीं था।” अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि केजरीवाल, जिन्हें इस मामले में आरोपी संख्या 18 बनाया गया था, के विरुद्ध भी कोई ठोस साक्ष्य नहीं रखा गया। इसी प्रकार, सिसोदिया और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ भी प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं हो सका। न्यायालय ने कहा कि आरोपों में पर्याप्त दम नहीं है और उपलब्ध साक्ष्य



अभियोजन की थ्योरी का समर्थन नहीं करतों। फैसले में अदालत ने CBI की जांच प्रक्रिया पर भी कड़ी टिप्पणी की। न्यायाधीश ने कहा कि विस्तृत चार्जशीट में कई कमियां पाई गईं और गवाहों के बयानों से अभियोजन के दावों की पुष्टि नहीं होती। अदालत के अनुसार, जांच एजेंसी सिसोदिया के खिलाफ पहली नजर में भी मामला बनाने में विफल रही। साथ ही, केजरीवाल को भी बिना ठोस प्रमाण के आरोपी बनाया गया। न्यायालय ने 23 में से किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सभी आरोपियों को औपचारिक रूप से बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि अभियोजन ने एक व्यापक साज़िश की कहानी प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन वह ठोस साक्ष्यों के अभाव में केवल अनुमान भर साबित हुई। यह निर्णय आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। कथित शराब नीति घोटाले को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लंबे समय तक जांच

और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। ऐसे में अदालत का यह फैसला राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “मैं करप्ट नहीं हूँ। कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया और मैं ईमानदार हैं।” उन्होंने इसे सच्चाई की जीत बताया और कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला उनके और उनकी पार्टी के लिए राहत लेकर आया है। वहीं, केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “सच की हमेशा जीत होगी।” उनके इस संदेश को पार्टी समर्थकों ने व्यापक रूप से साझा किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के साथ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी अध्याय समाप्त हो गया है। अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि बिना ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के किसी भी व्यक्ति को अपराधिक साज़िश में लिप्त नहीं ठहराया जा सकता।

भाजपा ने फैसले पर उठाए सवाल

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। फैसले के तुरंत बाद आप



नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित था और अदालत के निर्णय ने सच्चाई को सामने ला दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने अदालत के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अदालत ने आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है और यह एक तकनीकी मुद्दा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी फैसले का विस्तार से अध्ययन करने के बाद एक सुविचारित प्रतिक्रिया देगी। त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि यदि आरोप निराधार थे तो वे लगाए कैसे गए। भाजपा नेता और पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला निचली अदालत द्वारा सुनाया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि अतीत में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामलों में कड़े और निंदनीय टिप्पणियां की थीं। मालवीय ने कहा कि यह देखना बाकी है कि उच्च न्यायालयों में यह फैसला कितना टिकता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इस निर्णय के बाद जहां आम आदमी पार्टी इसे अपनी नैतिक जीत बता रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

डी.के. शिवकुमार के समर्थकों ने किया शक्ति प्रदर्शन कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व विवाद तेज

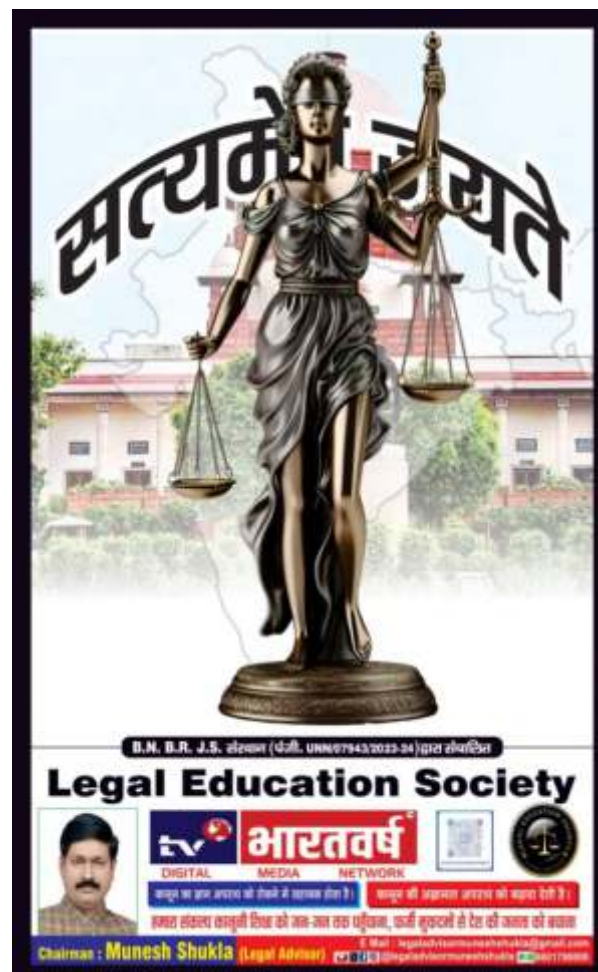
टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार में नेतृत्व को लेकर चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के समर्थक विधायकों ने बेंगलुरु के एक निजी होटल में शक्ति प्रदर्शन करते हुए पार्टी आलाकमान से शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद पर स्थापित करने का रास्ता साफ करने की मांग की है। मगाडी के विधायक एच.सी. बालकृष्ण द्वारा आयोजित इस बैठक में लगभग 40 समान विचारधारा वाले विधायक शामिल हुए। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर बालकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मिलन समारोह बताया गया, लेकिन अंदरूनी चर्चा पूरी तरह से नेतृत्व परिवर्तन पर केंद्रित थी। बालकृष्ण ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने शुक्रवार को बेंगलुरु नहीं रहने के कारण बृहस्पतिवार को सभी विधायकों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, “हमारे क्षेत्रों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा, हमें और पार्टी को भविष्य में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।” उन्होंने स्पष्ट किया कि विधायकों

को अलग-अलग बुलाने से समाधान नहीं निकलेगा, जबकि सभी का एकत्रित होना विषय पर खुली चर्चा को संभव बनाता है। कई विधायकों का मानना है कि इस विवाद के चलते उनकी राजनीतिक स्थिति और 2028 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। बालकृष्ण ने कांग्रेस के कर्नाटक इकाई अध्यक्ष पद में बदलाव की मांग पर कहा कि यदि शीर्ष नेतृत्व चाहे तो बदलाव किया जा सकता है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य पार्टी के भीतर स्थिति को अंतिम रूप देना है। उन्होंने कहा, “हम केवल अंतिम निर्णय चाहते हैं। अध्यक्ष बदलें या कोई और, यह मुख्य बात नहीं है। हमारी मांग है कि भ्रम समाप्त हो।” राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह बैठक छह मार्च से शुरू हो रहे कर्नाटक विधानसभा बजट सत्र से लगभग एक सप्ताह पहले हुई, जो समय बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। कुछ विधायकों ने संकेत दिया कि वे चाहते हैं कि शिवकुमार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का स्थान लें। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष नवंबर 2025 से तेज हुआ, जब कांग्रेस सरकार ने अपने ढाई वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। माना जाता है कि पार्टी नेतृत्व के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सिद्धरमैया



पहले ढाई वर्ष मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद शिवकुमार कार्यभार संभालेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई। शिवकुमार समय-समय पर इस संभावना का संकेत देते रहे हैं, जबकि सिद्धरमैया का कहना है कि वे पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। यह बैठक राज्य में नेतृत्व विवाद की गहराई और पार्टी आलाकमान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति को उजागर करती है।



अब आधार केंद्रों की जानकारी गूगल मैप पर उपलब्ध होगी

अब Google Maps पर देख सकेंगे Aadhaar केंद्र: लोकेशन, सेवाएं और अपॉइंटमेंट सभी एक जगह

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और तकनीकी कंपनी गूगल ने देशभर में अधिकृत आधार केंद्रों की जानकारी गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए साझेदारी की है। इस पहल के तहत लोग गूगल मैप पर खोज कर आसानी से पता कर सकेंगे कि कौन-सा आधार केंद्र वयस्क नामांकन, बच्चों का नामांकन या केवल पता और मोबाइल नंबर अपडेट जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, गूगल मैप पर प्रत्येक आधार केंद्र की सुगम्यता से जुड़ी जानकारी भी दिखाई जाएगी। इसमें दिव्यांगजन के अनुकूल ढांचा, पार्किंग की सुविधा और कार्य समय जैसी जानकारी शामिल होगी। अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा आने वाले महीनों में शुरू होने की संभावना है। इस सहयोग से देश भर में 60,000 से अधिक आधार केंद्रों तक लोगों की आसानी पहुंच सुनिश्चित होगी। यूआईडीएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) भुवनेश कुमार ने कहा, “आधार संख्या धारकों के जीवन को आसान बनाना हमारी प्राथमिकता है। यह सहयोग अधिकृत आधार केंद्रों तक पहुंच को सरल, तेज और पारदर्शी बनाएगा।” उन्होंने बताया कि इस पहल से उपयोगकर्ता समय की बचत कर सकेंगे और किसी भी केंद्र पर सेवाओं



की उपलब्धता की जानकारी पहले ही प्राप्त कर पाएंगे। साझेदारी के अगले चरण में यूआईडीएआई 'गूगल बिजनेस प्रोफाइल' के माध्यम से प्रत्येक आधार केंद्र की जानकारी का प्रबंधन करेगा। इससे केंद्रों के बारे में उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया का सीधे जवाब दिया जा सकेगा। आगे चलकर गूगल मैप के जरिये सीधे 'अपॉइंटमेंट' बुक करने की सुविधा भी शुरू करने की संभावना है, जिससे आधार सेवाओं का लाभ और सहज रूप से लिया जा सकेगा। गूगल इंडिया में रणनीतिक साझेदारी प्रमुख रोली अग्रवाल ने कहा कि इस पहल से

करोड़ों लोगों को भरोसेमंद सरकारी सेवाओं की जानकारी खोजने में आसानी होगी। इससे सरकारी ढांचे और आम लोगों के बीच की दूरी कम होगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर लोगों को जानकारी, सेवाएं और सुविधा एक ही जगह उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारत में डिजिटल प्रशासन को और मजबूत करेगी। यूआईडीएआई और गूगल के सहयोग से न केवल नागरिकों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि आधार केंद्रों की पारदर्शिता और

प्रभावशीलता भी सुनिश्चित होगी। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस पहल के लागू होने के बाद नागरिकों को नजदीकी आधार केंद्रों का पता लगाने, सेवा प्रकार की जानकारी हासिल करने और जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेने में आसानी होगी। इससे समय की बचत होगी और भीड़भाड़ में कमी आएगी। यूआईडीएआई और गूगल का यह सहयोग तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

डी गुकेश और अरविंद चिदंबरम प्राग शतरंज महोत्सव में दिखा रहे शानदार खेल



विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने प्राग अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर्स वर्ग के दूसरे दौर में उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक याकुबोव के साथ ड्रॉ खेला। लगातार दूसरी बाजी में सफेद मोहरों से खेल रहे गुकेश ने बढ़त बनाने का मौका नहीं भुनाया और दोनों खिलाड़ियों ने अंक साझा किए। पहले दौर में भी उन्होंने अमेरिका के हैस मोके नीमन के साथ ड्रॉ खेला था। वहीं, मौजूदा चैंपियन अरविंद चिदंबरम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका के हैस मोके नीमन को हराकर सभी को चौंका दिया। अरविंद ने अपनी नई पसंद फिलिडोर डिफेंस अपनाई और शुरुआती बढ़त हासिल करने वाले नीमन को महत्वपूर्ण मोड़ पर पराजित किया। इससे चेन्नई के इस खिलाड़ी को नोदिरबेक अब्दुसतोरोव से पहले दौर में मिली हार के बाद जीत का उत्साह मिला। एक अन्य मुकाबले में स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो ने नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फोस्ट को हराया। सात दौर के बचे हुए खेल में अब्दुसतोरोव, याकुबोव और स्थानीय खिलाड़ी डेविड नवारा 1.5 अंकों के साथ संयुक्त बढ़त पर हैं। इसके बाद गुकेश, अरविंद, वैन फोरेस्ट और गुइजारो आधे अंक से पीछे हैं। चोटियों में ईरान के परहम मगसूदलू, जर्मनी के शीर्ष वरीयता प्राप्त विंसेंट कीमर और नीमन ने नौ दौर के टूर्नामेंट में अभी तक आधा अंक ही हासिल किया है। चैलेंजर्स वर्ग में ग्रैंडमास्टर और विश्व महिला कप विजेता दिव्या देशमुख ने स्पेन के डैनियल युफ्फा के साथ ड्रॉ खेला। इसी वर्ग में खेल रहे एक अन्य भारतीय खिलाड़ी सूर्य शेखर गांगुली ने डेनमार्क के जोनास बुहल बिरे के साथ ड्रॉ खेलकर अपना खाता खोला। इस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने प्राग शतरंज महोत्सव में मजबूत शुरुआत की है और अगले दौरों में शीर्ष स्थान के लिए मुकाबला रोमांचक रहने की उम्मीद है।

क्रिकेट जगत में शोक की लहर रिंकू सिंह के पिता के निधन पर खिलाड़ियों ने संवेदना जताई



रिंकू सिंह के पिता के निधन पर बीसीसीआई ने जताई संवेदना खिलाड़ी वेस्टइंडीज मैच में शामिल नहीं होंगे

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह के पिता, खानचंद सिंह का 21 फरवरी को निधन हो गया। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और रिंकू के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। खानचंद सिंह लंबे समय से लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। तबियत अचानक बिगड़ने पर उन्हें ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। शुक्रवार की सुबह 4:36 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बीसीसीआई सचिव ने पुष्टि की कि इस दुखद स्थिति के कारण रिंकू सिंह रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले सुपर-8 मैच में टीम के साथ कोलकाता नहीं जाएंगे। इस मुकाबले को भारतीय टीम के लिए वचुअल क्वार्टर फाइनल की तरह महत्व दिया जा रहा है। सैकिया ने कहा कि रिंकू से जुड़ी किसी भी अपडेट को जल्द ही साझा किया

जाएगा। रिंकू अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चेन्नई से सुबह 5 बजे रवाना हो गए। रिंकू के इस व्यक्तिगत नुकसान के समय, बीसीसीआई और टीम प्रबंधन उनके साथ खड़े हैं। क्रिकेट जगत में रिंकू सिंह की फॉर्म और उपलब्धियों के बीच यह व्यक्तिगत क्षति उनके लिए चुनौतीपूर्ण समय है। बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों और स्टाफ से इस कठिन समय में रिंकू के परिवार का सम्मान और सहयोग करने का आग्रह किया है। रिंकू सिंह के परिवार और टीम के साथी इस दुखद घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, और भारतीय क्रिकेट प्रेमी भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इस घटना से यह साफ है कि खेल और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना खिलाड़ियों के लिए हमेशा आसान नहीं होता। रिंकू की अनुपस्थिति में टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल में नए संयोजन पर निर्भर रहना होगा।

अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अर्धशतक से आलोचकों का किया मुंह बंद

भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की है। अभिषेक ने टी20 विश्व कप 2026 के सुपर आठ मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाकर टीम को मजबूती से आगे बढ़ाया और अपनी फॉर्म में वापसी की। गुरुवार को खेले गए इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर 55 रन बनाए और भारत को चार विकेट पर 256 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। यह पारी अभिषेक के लगातार चार फ्लॉप प्रदर्शन के बाद आई और उन्होंने आलोचकों को चुप करा दिया। गावस्कर ने कहा, “हम जानते हैं कि अभिषेक शर्मा कितने अच्छे बल्लेबाज हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ 55 रन की इस पारी से उन्होंने अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने अपना स्वाभाविक खेल खेलने से पहले परिस्थितियों को समझा और रणनीति के साथ खेला।” गावस्कर ने अभिषेक की रक्षात्मक शैली की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अभिषेक ने ऑफ स्पिनरों का सम्मान करते हुए किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया। “उन्होंने शांत और संयमित तरीके से खेलते हुए कई गेंदों को रोका। मुझे यह देखकर हैरानी हुई क्योंकि आमतौर पर अभिषेक को इतनी संयमित और रक्षात्मक पारी खेलते नहीं देखते हैं।” इस मैच में



अभिषेक के खेल ने भारत को तूफानी शुरुआत दिलाई और बड़े स्कोर की नींव रखी। उनके योगदान से टीम का मनोबल बढ़ा और सुपर आठ में भारत की स्थिति मजबूत हुई। गावस्कर ने यह भी कहा कि अभिषेक की यह पारी यह साबित करती है कि वह न केवल प्रतिभाशाली हैं, बल्कि बड़े मैचों में दबाव में शांत और रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम हैं। टी20 विश्व कप 2026 में इस प्रदर्शन के बाद अभिषेक शर्मा को टीम की प्रमुख बल्लेबाजों में गिना जाने लगा है। इस तरह, जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा की पारी टीम इंडिया के लिए क्लच प्रदर्शन साबित हुई और आलोचकों के सामने उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया।

भारत बनाम वेस्टइंडीज,

सेमीफाइनल की राह तय करेगी रविवार की भिड़ंत

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक टूर्नामेंट में अब भारतीय क्रिकेट टीम का सामना वेस्टइंडीज से होने वाला है। यह मुकाबला 1 मार्च (रविवार) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा और इसे किसी नॉकआउट मैच से कम नहीं माना जा रहा है। जीत हासिल करने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर टूर्नामेंट में यहीं समाप्त हो जाएगा। भारतीय टीम का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड रहा है। अब तक दोनों टीमों के बीच खेले गए 30 मुकाबलों में से भारत ने 19 में जीत दर्ज की है। वहीं, वेस्टइंडीज ने 10 मैचों में जीत हासिल की और एक मुकाबला बेनतीजा रहा। हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप की पृष्ठभूमि में वेस्टइंडीज का पलड़ा भारत के खिलाफ भारी रहा है। अब तक टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच

चार मुकाबले हुए हैं, जिनमें से वेस्टइंडीज ने तीन जीत हासिल की है और भारत केवल एक बार विजयी रहा। इस प्रतिद्वंद्विता में 2016 का सेमीफाइनल मुकाबला विशेष रूप से यादगार है, जब वेस्टइंडीज ने भारत को हराकर टूर्नामेंट में अपनी बढ़त कायम रखी थी। इस बार के मुकाबले में भारत जीत दर्ज करने के लिए पूरी तैयारी में है। कोचिंग स्टाफ और कप्तान ने खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया है। पिच की परिस्थितियों और विकेट की स्थिति को देखते हुए टीम ने रणनीति तैयार की है, जिसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलन बनाने पर ध्यान दिया गया है। वेस्टइंडीज की टीम भी इस मैच में दबदबा बनाने के इरादे से उतरेगी। टी20 वर्ल्ड कप में उनका अनुभव और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए यह मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होने



की उम्मीद है। इस प्रकार, 1 मार्च को होने वाला यह मुकाबला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक मैचों में शुमार होने जा रहा है, जहां जीत हासिल करने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।

रेस्क्यू और इवैकुएशन की हो रही तैयारियां

ईरान से कैसे लौटेंगे फंसे भारतीय

पिछले साल ईरान और इजरायल के बीच जब तनाव के हालात बने थे, तब ऑपरेशन सिंधु (जून 2025) के तहत वहां रहने वाले भारतीयों को सकुशल वापस लाया गया था, अभी तनाव बढ़ रहा है, लेकिन ईरान का एयर स्पेस अब भी खुला है और कमर्शियल फ्लाइट भारत के लिए आ रही हैं.

अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने लोगों को तुरंत ईरान छोड़ने की एडवाइजी जारी की है. इस बीच ईरान में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्रा और कामकाजी प्रोफेशनल्स सुरक्षित वापस आने की तैयारी में हैं. ऐसे में जानते हैं कि वहां कितने इंडियन



ईरान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं भारतीय नागरिक (Representational Photo - Pexels)

रह रहे हैं और उन्हें कैसे वापस लाया जाएगा. विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड के मुताबिक, ईरान में कुल 10765 प्रवासी भारतीय रहते हैं. इनमें 10320 एनआरआई और 445 भारतीय मूल के हैं. इनमें से कई स्टूडेंट्स हैं और काफी लोग वहां शिक्षा, इंजीनियरिंग और

कारोबार से जुड़े क्षेत्र में काम करते हैं. अधिकांश भारतीय ईरान के प्रमुख शहरों तेहरान, इस्फान और जाहेदान में रहते हैं. अभी ईरानी हवाई क्षेत्र खुला है और वाणिज्यिक उड़ानें चल रही हैं. इसलिए सरकार वहां रह रहे लोगों को फंसा हुआ नहीं मानती है. हालांकि, तेहरान स्थित

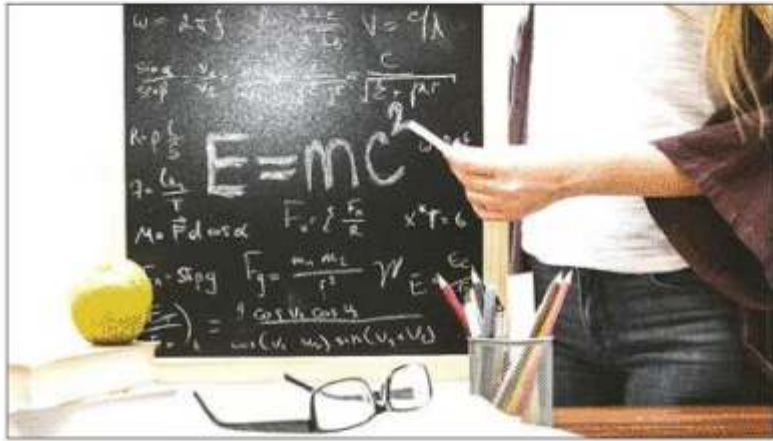
भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय को तुरंत ईरान छोड़ देने की एडवाइजरी जारी की है और लगातार वहां रह रहे लोगों की मदद के लिए उनके संपर्क में है. लोगों को अपने पासपोर्ट और यात्रा संबंधी डॉक्यूमेंट तैयार रखने को कहा गया है. ☹



सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वालों से ज्यादा कमाई ट्रक ड्राइवर की

आजकल कई डिग्री होल्डर युवाओं को अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है और कम सैलरी में गुज़ारा करना पड़ रहा है. ऐसे में दिल्ली के एक कारोबारी का दावा लोगों को चौंका रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी का एक ट्रक ड्राइवर पढ़े-लिखे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स से ज्यादा कमाई कर रहा है. इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर तेज बहस शुरू हो गई है. ☹

महिला टीचर पर लगे आरोपों से छिड़ी बहस



एक महिला टीचर ने बेघर स्टूडेंट को पढ़ाई में मदद के नाम पर अपने घर में पनाह दी. फिर उसे शराब पिलाना शुरू किया. इसके बाद उसका यौन शोषण करने लगी. स्टूडेंट भी फिर से बेघर हो जाने के डर से इसका विरोध न कर सका और सबकुछ सहता रहा. आखिरकार, पासआउट होने के

बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी टीचर की सारी करतूत पुलिस को बता दी. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लोरिडा की 49 साल की शिक्षिका पर बेघर छात्र को अपने घर में पनाह देने के बाद उसके साथ लिच-इन रिलेशनशिप में रहने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है. ☹

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही घटना

सोने की अफवाह पर खोद डाली खेत

जोहान्सबर्ग से 30 मील पूर्व में स्थित एक कस्बे में मशीनों से कई गहरे गड्ढों को भरा जा रहा है.

यह एक काम एक ऐसी खोज का अंत था, जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक अफवाह से हुई. किसी जमाने में इस कस्बे के आसपास सोने का खनन होता था. जब यहां से सोना मिलना बंद हो गया तो खनन का काम भी रोक दिया गया और पूरा इलाका वीरान हो गया. अब एक बार फिर से ये पूरा इलाका कुछ दिनों के लिए सोने की खोज की वजह से चर्चा में आ गया था. यहां दर्जनों भाग्य आजमाने वाले लोग पहुंचे और फावड़ों और मशीनों से आसपास के खेतों की खुदाई करने लगे. दो सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर जोहान्सबर्ग के पास एक पुराने



खनन शहर में सोना मिलने की अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई. किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि स्प्रिंग्स नामक खनन शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बस्ती में कच्ची सड़क के किनारे एक खेत में बाड़ के खंभे के लिए गड्ढा खोदते समय

सोना मिला है. इसके बाद पास के गांव गुगुलेशु के कई बेरोजगार निवासी यहां आकर खुदाई के काम में जुट गए. द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय पार्षद डीन स्टोन ने बताया कि सैकड़ों मील दूर से यहां लोग आने लगे और सोने की खोज में जुट गए. ☹

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार साथ नजर आए

उदयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को बॉलीवुड और टॉलीवुड की चर्चित जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के बाद पहली झलक देखने को मिली। दोनों की एयरपोर्ट पर साथ में मौजूदगी पपाराजी के कैमरों में कैद हो गई। लाल रंग के आउटफिट में रश्मिका मंदाना नई दुल्हन का खुमार लिए नजर आईं, जबकि दूल्हा विजय देवरकोंडा भी कैमरे के सामने हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करते दिखे। रश्मिका और विजय की शादी गुरुवार को संपन्न हुई। इस शादी में तेलुगू हिंदू और कोडवा रीति-रिवाजों का मिश्रण देखने को मिला। शादी समारोह में परिवारजन और करीबी मित्र शामिल हुए। शादी के बाद कपल ने कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा कीं, जिसमें दोनों की खुशी साफ झलक रही थी। शादी के अगले दिन, यानी शुक्रवार को रश्मिका और विजय अपने परिवार के साथ उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां दोनों की पहली झलक देखने के लिए मीडिया और फैंस काफी उत्साहित थे। एयरपोर्ट पर रश्मिका का लाल रंग का पारंपरिक परिधान और विजय का सुरुचिपूर्ण लुक लोगों का ध्यान खींच रहा था। दोनों ने हाथ जोड़कर अपने फैंस और मीडिया का स्वागत किया। रश्मिका की मुस्कान और विजय की विनम्रता ने इस मौके को और भी खास बना दिया। परिवार के साथ रश्मिका और विजय ने एयरपोर्ट पर कुछ समय बिताया

और फिर उड़ान भरने के लिए रवाना हुए। इस दौरान दोनों की केमिस्ट्री और खुशी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। सोशल मीडिया पर भी उनकी यह झलक तेजी से वायरल हो गई। शादी को लेकर दोनों की जोड़ी पहले ही काफी चर्चित थी। फैंस ने लंबे समय से उनकी शादी की प्रतीक्षा की थी और अब शादी के बाद उनका पहला पब्लिक आउटिंग पल काफी रोमांचक और यादगार

साबित हुआ। इस शादी ने बॉलीवुड और टॉलीवुड के फैंस को खुशी के साथ-साथ उत्सुकता भी दी है कि रश्मिका और विजय अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करेंगे। शादी की झलक और एयरपोर्ट पर दोनों का स्टाइलिश अंदाज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और फैंस दोनों की जोड़ी को खूब प्यार दे रहे हैं।



लखनऊ में शुरू हुआ 2 दिवसीय

“उत्तर प्रदेश मीन महोत्सव और एक्वा एक्सपो-2026”

लखनऊ में दो दिवसीय "उत्तर प्रदेश
मीन महोत्सव और एक्वा एक्सपो-
2026" शुरू हुआ। कार्यक्रम में मत्स्य
पालन के आधुनिक तकनीकी
प्रशिक्षण, योजनाओं की जानकारी
और किसानों की समस्याओं पर चर्चा
हुई, ताकि उन्हें लोन और सरकारी
सुविधाओं का सही लाभ मिल सके।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से आज से दो दिवसीय “उत्तर प्रदेश मीन महोत्सव और एक्वा एक्सपो-2026” का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम 27 और 28 फरवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश सरकार के मत्स्य विकास कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन अवसर पर मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने मत्स्य पालन क्षेत्र में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं और बैंक लोन की प्रक्रिया में उत्पन्न समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कई बार विभाग से मत्स्य पालक का सर्टिफिकेट मिलने के बावजूब बैंक वाले किसानों को लोन के लिए दौड़ाते हैं और प्रक्रिया जटिल बना देते हैं। इस पर उन्होंने जोर दिया कि किसानों को आसानी से और शीघ्र लोन मिलना चाहिए, ताकि उनका काम प्रभावित न हो। इस अवसर पर मत्स्य सहकारी समिति के अध्यक्ष वीरू साहनी ने भी प्रशासन पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि एसीटीएम द्वारा किसानों के उठा देने की प्रक्रिया में एडिटर द्वारा नहीं की जा रही है और किसानों को निरंतर परेशान किया जा रहा है। वीरू साहनी ने मुख्यमंत्री से अग्रह



किया कि ऐसे अधिकारियों से पावर छिन ली जाए ताकि मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने महोत्सव के दौरान उपस्थित महिला मत्स्य पालक से सीधे सवाल किया कि क्या उन्हें विभाग की योजनाओं का लाभ मिला या नहीं। महिला ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इस पर अवनीश अवस्थी ने डायरेक्टर को तुरंत बुलाकर निर्देश दिए कि इस महिला का नाम नोट किया जाए और उसे योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया की रिपोर्ट उन्हें दी जाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाएं वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रही हैं। महोत्सव में मत्स्य पालन से जुड़े विभिन्न प्रदर्शनों और तकनीकी जानकारीयों को प्रदर्शित किया गया।

इसमें आधुनिक मत्स्य पालन तकनीक, जलाशय प्रबंधन, मछली पालन के लिए नवीनतम उपकरण और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। आयोजन का उद्देश्य मत्स्य पालन में नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना, उनके व्यवसाय को लाभकारी बनाना और क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस अवसर पर मत्स्य पालकों के अनुभव और समस्याओं को सुनने पर जोर दिया। उपस्थित किसानों ने विभिन्न मुद्दों जैसे लोन वितरण, योजनाओं का लाभ, ठेका प्रक्रिया और विभागीय दायरों में विलंब की शिकायत की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इन शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा और भविष्य में पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। इस महोत्सव में मत्स्य

पालन से जुड़े स्टाल, सरकारी योजनाओं की जानकारी, तकनीकी प्रशिक्षण सत्र और प्रेरक भाषणों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है, बल्कि किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करना और उन्हें सरकारी योजनाओं का सही लाभ दिलाना भी है। उत्तर प्रदेश मीन महोत्सव और एक्वा एक्सपो-2026 किसानों और मत्स्य पालन विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने का अवसर प्रदान कर रहा है, जिससे राज्य में मत्स्य पालन उद्योग में सुधार और वृद्धि हो सके। इस दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ सत्र, प्रदर्शनी और कृषि प्रौद्योगिकी के नए उपकरणों का प्रदर्शन होगा, जो किसानों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे।

**आशियाना में कारोबारी
की हत्या के बाद बेटे ने
शव के टुकड़े किए
वेब सीरीज से सीखा तरीका**

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लेखनरूक के आशियाना क्षेत्र के सेक्टर एल में रहने वाले पैथालॉजी संचालक और शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह (49) की हत्या के मामले में चौकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस पृष्ठताछ में सामने आया है कि हत्या के बाद उनका बेटा अक्षत शव को ठिकाने लगाने को लेकर परेशान था। आरोपी ने बताया कि शव का वजन अधिक होने के कारण वह उसे अकेले कार में लादकर कहीं ले जाने में सक्षम नहीं था। जांच में यह भी सामने आया कि अक्षत ने वेब सीरीज 'वध' देखी थी, जिससे उसने शव को काटकर ठिकाने लगाने का तरीका सीखा। वेब सीरीज में आरी से शव के टुकड़े करने का दृश्य दिखाया गया था, जिसे उसने अपनाने का निर्णय लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पहले ऑनलाइन चाकू मंगाया और उससे शव को काटने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बाद वह घर से बाहर निकला और दो आरी खरीदकर लाया। इन्हीं आरी की मदद से उसने शव के टुकड़े किए। सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने यूट्यूब पर भी शव को ठिकाने लगाने से जुड़े वीडियो देखे थे और शव काटने के तरीके की जानकारी जुटाई थी। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद अक्षत ने अपनी छोटी बहन कृति से कहा था कि वह परेशान न हो, सब कुछ वह संभाल लेगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी के मन में अपने पिता के प्रति गहरी नफरत थी, जिसके चलते वह इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने में नहीं हिचकिचाया। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन का LDA के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, किसानों ने मुआवजे की मांग दोहराई

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयवाद के सदस्यों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के खिलाफ जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। दर्जनों किसान हाथों में डंडा, झंडा और हथिया लेकर एलडीए मुख्यालय पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल महिला और पुरुष किसानों ने नारे लगाते हुए कहा, “जो ना माने झंडे से उसे समझाओ डंडे से।” किसान एलडीए के प्रतीकात्मक पुतले पर चोर लिखा और उसकी डंडों से पिटाई करते हुए हथिया से काटा। इसके बाद किसान अपनी मांगों के समर्थन में एलडीए के मुख्य द्वार पर दरी बिछाकर बैठ गए। किसान नेता अशोक यादव ने बताया कि किसानों को सालों से सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 40 वर्ष पहले, 1984 में किसानों की जमीन एलडीए द्वारा अधिकृत की गई थी। उस समय मुआवजा 84 पैसे प्रति इकाई तय हुआ। किसानों और एलडीए के बीच वार्ता के बाद इसे बढ़ाकर 2.5 रुपए किया गया। कुछ किसानों ने कोर्ट का सहारा लिया, जिसके बाद 4.60 रुपए प्रति इकाई मुआवजा तय हुआ। 2016 में कोर्ट ने अंतिम मोहर लगाते हुए सभी किसानों को यह राशि देने का आदेश दिया। अशोक यादव ने आरोप लगाया कि एलडीए अब कह रहा है कि उनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, इसलिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण के समय किसानों को रोजगार, आवास, गांव के विकास और किसान भवन जैसी कई सुविधाओं का वादा किया गया था, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ। किसानों ने बताया कि लखनऊ का किसान आज दर-दर भटकने को मजबूर है। पहले तीनों शमशान स्थल थे, लेकिन अब केवल एक बचा है। एलडीए ने वादा किया था कि 400 चबूतरे विराज खंड



में दिए जाएँ ताकि किसान अपना रोजगार कर सकें, लेकिन केवल 120 चबूतरे ही दूसरे हलाके में उपलब्ध कराए गए। इसका असर यह हुआ कि किसान परिवारों की महिलाएँ आज झाड़ू-पोछा करने के लिए दूसरों के घरों पर निर्भर हैं। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि भूमि अधिग्रहण के समय किए गए वादों में से कोई भी पूरा नहीं हुआ। प्रशासन और एलडीए अधिकारी मिलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि देश में अन्नदाता की यह स्थिति गंभीर है और उन्हें दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस प्रदर्शन में किसानों ने मुआवजे की राशि और जमीन अधिग्रहण के समय किए गए वादों के पालन की मांग की और चेताया कि उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

हल्दीराम वेयरहाउस से एक्सपायर्ड मिठाई, 55 लाख रुपये मूल्य की सामग्री जब्त

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने गुरुवार को शहर के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान हल्दीराम के वेयरहाउस सहित कई कोल्ड स्टोरेज और संस्थानों से भारी मात्रा में मिलावटी और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ बरामद किए गए। विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। फैजुल्लागंज स्थित हल्दीराम के स्टोरेज में छापेमारी के दौरान टीम को 1 क्विंटल 12 किलो एक्सपायर्ड सोनपापड़ी और राजभोग बरामद हुए। अधिकारियों ने लगभग 45,000में कौन हैं/पेड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेठा और गुजिया के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इसी अभियान में ऐशबाग स्थित स्वरूप कोल्ड स्टोरेज पर भी बड़ी कार्रवाई की गई। यहां से 8,499 और 378 किलो खोया जन्त किया गया। कुल मिलाकर इस अभियान में 10,415 किलो खाद्य पदार्थ जन्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 55.9 बताई जा रही है। इसके अलावा महानगर स्थित 'ग्लोब कैफे' से



भी पनीर और गुजिया के नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विभागीय टीम ने 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' के माध्यम से मड़ियांव क्षेत्र में जागरूकता अभियान भी चलाया। अधिकारियों ने नागरिकों को खुले में बिकने वाले चटकीले रंगों वाले पापड़ और कचरी के सेवन से बचने की सलाह दी। बताया गया कि इन उत्पादों में प्रतिबंधित सिंथेटिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो पाचन तंत्र की गड़बड़ी, एलर्जी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति में देरी पर सख्ती

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश शासन ने सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को दिए जाने वाले सेवायोजन (कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट) के मामलों में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की ओर से जारी शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सभी प्रकरणों का निस्तारण अधिकतम तीन माह के भीतर पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी यह आदेश सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजा गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (यथासंशोधित) नियमावली-1974 का उद्देश्य सेवाकाल में आकस्मिक मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक संकट से उबारना है। शासन के संज्ञान में आया है कि कई मामलों में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, जिससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियमावली के तहत आने वाले मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से निस्तारण किया जाए। शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति का उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि संकटग्रस्त परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करना है।

मेस के दूषित भोजन से छात्रा बीमार, प्रदर्शन कर रही छात्राओं की मांगें जारी

लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस में गुरुवार सुबह मेस का खाना खाने से एक और छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। बीमार छात्रा को तुरंत मेडिकल हेल्प प्रदान की गई। घटना के बाद कुलपति और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य मौके पर पहुंचे और छात्राओं से स्थिति को समझने का प्रयास किया। बीमार छात्रा, गंगा हॉस्टल में रहने वाली BBA की छात्रा कशिश, मेस का भोजन खाने के बाद अचानक बीमार हो गई। स्थिति गंभीर होने पर उसे डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए ले जाया गया। इस घटना के बाद आक्रोशित छात्राओं ने मेस में ताला लगा दिया और कुलपति के आने तक उसे खोलने से मना कर दिया। छात्राओं का कहना था कि वे प्रोवोस्ट को हटाने की मांग पर अड़ी हुई हैं। हॉस्टल प्रशासन छात्राओं की नाराजगी को देख बैकफुट पर आ गया। गुरुवार सुबह का नाश्ता मेस में तैयार नहीं किया गया। कुछ देर बाद कुलपति प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्वयं

छात्राओं से वार्ता की और उनका विश्वास जीतकर मेस का ताला खोला गया। इसके बाद लंच तैयार किया गया। घटना के बाद कुलपति ने कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा को निर्देश दिए कि मेस संचालक को नोटिस जारी किया जाए। छात्राओं ने अपनी शिकायतें लिखकर दर्ज कराईं। कुलपति ने समस्या की गंभीरता को देखते हुए डीन लॉ फैकल्टी को भी निर्देश दिए कि वे बुधवार को धरना प्रदर्शन करने वाली छात्राओं की समस्याओं को सुनें और उनका समाधान निकालने का प्रयास करें। इस पूरे घटनाक्रम से विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्राओं के बीच तनातनी बढ़ गई है। छात्राओं का कहना है कि मेस में बार-बार दूषित भोजन दिया जा रहा है और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती। कुलपति ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर समस्या का त्वरित समाधान करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निगरानी बढ़ाने का आश्वासन दिया। विश्वविद्यालय के न्या



कैपस में यह घटना छात्राओं और प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर छात्राएं सतर्क हैं और प्रशासन को भी तत्काल कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया है। अब यह देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्राओं की मांगों और मेस की गुणवत्ता सुधारने के लिए कितनी प्रभावी कार्रवाई करता है।

उन्नाव पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान में बड़ी सफलता

12 अपराधियों को आजीवन कारावास

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष अभियान के अंतर्गत डेढ़ माह से भी कम समय में 12 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पुलिस और अभियोजन विभाग के समन्वित एवं सुनियोजित प्रयासों का परिणाम है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, यह अभियान पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को त्वरित और सुनिश्चित सजा दिलाना है। इसके लिए लंबित और महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया गया है तथा उनकी नियमित समीक्षा की जा रही है। एसपी सिंह ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक की अवधि में कुल 103 मामलों में 118 अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में सुनवाई पूरी कराई गई। इन मामलों में साक्ष्यों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिससे अदालत में अभियोजन पक्ष की स्थिति मजबूत रही। परिणामस्वरूप 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि दो अभियुक्तों को 20 वर्ष या उससे अधिक की कठोर सजा दी गई। इसके अतिरिक्त, दो अभियुक्तों को 10 से 14 वर्ष की सजा सुनाई गई। पांच अभियुक्तों को 5 से 9 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया गया, जबकि



51 अभियुक्तों को 5 वर्ष से कम अवधि की सजा मिली। वहीं, 46 अभियुक्तों के मामलों में न्यायालय ने उनके द्वारा पहले ही जेल में बिताई गई अवधि को सजा के रूप में मान्य कर लिया। इस प्रकार विभिन्न श्रेणियों में बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण हुआ। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इतने कम समय में गंभीर मामलों में सजा दिलाना आसान नहीं था। इसके लिए विवेचना को समयबद्ध और साक्ष्य-आधारित बनाया गया। जांच अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे वैज्ञानिक साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी प्रमाणों को मजबूत करें, ताकि न्यायालय में अभियोजन पक्ष प्रभावी ढंग से अपनी दलील रख सके। अभियोजन विभाग के साथ नियमित समन्वय बैठकें भी

आयोजित की गईं, जिनमें प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले की प्रगति की समीक्षा की गई। 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत हत्या, दुष्कर्म, लूट, संगठित अपराध और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों को प्राथमिकता दी गई। इन मामलों में त्वरित कार्रवाई और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिससे दोषियों को सजा दिलाई जा सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। पुलिस प्रशासन का मानना है कि ऐसे अभियानों से न केवल अपराधियों में भय का माहौल बनता है, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास भी मजबूत होता है। एसपी सिंह ने कहा कि जनपद में अपराध और अपराधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है। उन्होंने दोहराया कि पीड़ितों को न्याय दिलाना पुलिस की

सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभियान के अंतर्गत लंबित मामलों की निरंतर समीक्षा की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके और दोषियों को दंडित किया जा सके। पुलिस प्रशासन का दावा है कि 'ऑपरेशन कनविक्शन' के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अपराधियों में सख्त कार्रवाई का संदेश गया है और कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इसी प्रकार गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर त्वरित सजा दिलाने का प्रयास जारी रहेगा, जिससे जनपद में सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण स्थापित किया जा सके।



उन्नाव के पकराबुजुर्ग गांव में राशन वितरण में अनियमितता ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

बीधापुर तहसील के पकराबुजुर्ग गांव में राशन वितरण में अनियमितताओं को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले तीन महीनों से राशन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्होंने पनहन-पुरवा पाटन रोड जाम कर दिया। इस घटना के बाद प्रशासन ने कोटेदार की दुकान को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार राजू पिछले तीन महीनों से ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगावाकर राशन वितरण दिखाता रहा, लेकिन लाभार्थियों को एक दाना भी अनाज नहीं मिला। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि केवाईसी के नाम पर प्रत्येक राशन कार्ड धारक से 50 रुपये की अवैध वसूली की गई। इस अनियमितता के कारण कई परिवारों के सामने खाद्यान्न का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरी करके गुजर-बसर करने वाले परिवारों को बाजार से महंगा राशन खरीदना पड़ रहा है। महिलाओं ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि बच्चों का पेट

भरना मुश्किल हो गया है, जबकि सरकारी योजना के तहत मिलने वाला अनाज ही उनका एकमात्र सहारा है। सड़क जाम की सूचना मिलते ही सप्टाई इंस्पेक्टर मनोज और बिहार थाना प्रभारी राहुल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की और मामले की जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में अनियमितता के संकेत मिलने पर राशन की दुकान को सीज कर दिया गया। प्रशासन ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि होली से पहले सभी पात्र लाभार्थियों को बकाया राशन वितरित कराया जाएगा। साथ ही, पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम समाप्त किया और यातायात बहाल हो सका। इस घटना ने सरकारी राशन वितरण प्रणाली में मौजूद कमियों और ग्रामीणों की मुश्किलों को उजागर किया है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी।



उन्नाव में 42 दिन का मेगा ब्लॉक लखनऊ-कानपुर रेलखंड पर यात्रियों को होगी असुविधा

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

। लखनऊ-कानपुर रेलखंड पर गंगापुल के पास हाई बीम स्लीपर बदलने और डाउन लाइन पर व्यापक मरम्मत के लिए रेलवे ने 42 दिनों का मेगा ब्लॉक घोषित किया है। यह कार्य 2 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक चलेगा। इस दौरान रेलवे यात्री सेवा में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह कार्य गंगाघाट रेलवे स्टेशन के निकट गंगापुल पर किया जाएगा। लंबे समय से पुल पर ट्रैक और स्लीपर्स के रखरखाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने हाई बीम स्लीपर बदलने का निर्णय लिया है, ताकि भविष्य में संभावित दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सके। मेगा ब्लॉक के कारण कई पैसेंजर, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें प्रभावित होंगी। कुछ ट्रेनों को पूरी तरह निरस्त किया जाएगा, जबकि कई को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि प्रभावित ट्रेनों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें। यह रेलखंड दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली लंबी दूरी की

ट्रेनों के लिए एक प्रमुख मार्ग है। लखनऊ-कानपुर रूट प्रदेश के सबसे व्यस्त रेलमार्गों में से एक है। इस कारण दैनिक हजारों यात्री, नौकरीपेशा लोग और छात्र इस मार्ग का उपयोग करते हैं। मेगा ब्लॉक के दौरान उन्हें विशेष रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि अप लाइन पर ट्रेनों का संचालन सीमित रूप से जारी रहे। इंजीनियरिंग विभाग की टीमें दिन-रात काम करेंगी और ट्रैक मशीनों तथा आधुनिक उपकरणों की मदद से स्लीपर बदलने की प्रक्रिया तेज गति से पूरी की जाएगी। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों और रिफंड प्रक्रिया के दिशा-निर्देश जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित स्टेशन से जानकारी प्राप्त करें। इस मेगा ब्लॉक से यात्रियों को असुविधा हो सकती है, लेकिन रेलवे का कहना है कि यह कार्य पुल और ट्रैक की मजबूती सुनिश्चित करने और भविष्य में दुर्घटनाओं की संभावना कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने उन्नाव कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण किया



टीवी भारतवर्ष उन्नाव

लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने गुरुवार दोपहर उन्नाव कलेक्ट्रेट का अचानक औचक निरीक्षण किया। उनकी अनपेक्षित उपस्थिति से प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल मच गई। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने कमिश्नर का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सीधे प्रशासनिक कार्यालय का दौरा किया और जिलाधिकारी के साथ विभिन्न अभिलेखों और संचालित योजनाओं की समीक्षा शुरू की। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने विभिन्न शाखाओं के रजिस्टर, लंबित प्रकरणों की फाइलें, राजस्व अभिलेख और जनशिकायत निस्तारण से संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति, राजस्व वसूली, भूमि विवादों के निस्तारण और कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी ली। कमिश्नर ने लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने और जनसुनवाई के माध्यम से शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। औचक निरीक्षण की खबर मिलते ही कई विभागों के अधिकारी अपनी शाखाओं में सक्रिय हो गए। निरीक्षण का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयपालन को सुनिश्चित करना बताया गया।

अनिवार्य टीईटी के विरोध में शिक्षकों का धरना, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ सहित विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने बीएसए कार्यालय स्थित धरना स्थल पर अनिवार्य टीईटी के विरोध में प्रदर्शन किया। करीब तीन घंटे तक चले धरने के बाद शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष बृजेश पांडेय ने कहा कि शिक्षकों के उत्पीड़न की सीमा पार हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार संशोधन कर इस "काले कानून" को वापस नहीं लेती है तो मार्च के तीसरे सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में देशभर के बेसिक शिक्षक एकत्र होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। महामंत्री गजेन्द्र वर्मा ने कहा कि शिक्षक लंबे समय से पुरानी पेंशन, प्रतिकर अवकाश समेत अन्य मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अब तो नौकरी ही छीनने का प्रयास किया जा रहा है। जूनियर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अनुपम मिश्र ने भी कहा कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली में शिक्षकों का शंखनाद होगा। महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष मंजू कुनौजिया ने कहा कि पहले भी शिक्षकों पर कई नियम थोपे जा चुके हैं और अब नौकरी पर संकट खड़ा कर दिया गया है। वहीं एससी-एसटी बेसिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश ने आरोप लगाया कि समाज को बांटकर और शिक्षकों में एकता तोड़कर निजीकरण लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिक्षक इसमें सफल नहीं होने देंगे। धरने में संजय सिंह, विनोद तिवारी, अजय कटियार, सूर्यकांत सिंह, विश्वनाथ सिंह, संदीप द्विवेदी, प्रदेश द्विवेदी, शशांक भूषण तिवारी, विनोद सिंह समेत सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 121 जोड़े विवाह बंधन में बंधे

हड़हा स्थित डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 121 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इनमें 118 हिंदू जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सात फेरे लिए, जबकि तीन मुस्लिम जोड़ों का निकाह संपन्न कराया गया। समारोह का आयोजन समाज कल्याण विभाग की ओर से किया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी गौरांग राठी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया और उपहार भेंट किए। सदर विधायक पंकज गुप्ता के पुत्र प्रखर गुप्ता ने भी नवदंपतियों को उपहार वितरित किए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पहुंचकर जोड़ों को शुभकामनाएं दीं। हिंदू जोड़ों का विवाह आचार्यों द्वारा वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार

संपन्न कराया गया। वहीं मुस्लिम जोड़ों का निकाह धार्मिक परंपराओं के अनुसार कराया गया। समारोह में बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग मौजूद रहे। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीप्रकाश पांडेय ने बताया कि शासन की योजना के तहत प्रत्येक वधू के खाते में 60 हजार रुपये की धनराशि भेजी गई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये मूल्य का घरेलू सामान प्रदान किया गया। विवाह समारोह में खानपान पर प्रति जोड़ा 15 हजार रुपये व्यय किए गए। समारोह में मोहान क्षेत्र से 31, बांगरमऊ और सफीपुर से 26-26, पुरवा से 24, सदर से 10 तथा भगवंतनगर से चार जोड़ों ने भाग लिया। आयोजन को सफल बनाने में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 28 फरवरी 2027 तक बढ़ा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 28 फरवरी 2027 तक बढ़ा दिया। पूर्व आईएएस अवस्थी ने एक्सप्रेसवे निर्माण, कानून व्यवस्था सुधार और दिव्यांग सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका अनुभव आगामी विधानसभा चुनाव और प्रशासनिक योजनाओं में अहम भूमिका निभाएगा।

टीवी भारतवर्ष उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ा दिया गया है। अब वह 28 फरवरी 2027 तक मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में सेवा देंगे। यह निर्णय उनकी प्रशासनिक दक्षता, योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन और योगी सरकार में निभाए गए महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए लिया गया है। इस सेवा विस्तार के साथ ही अवस्थी की भूमिका राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णयों में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। अवनीश कुमार अवस्थी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 19 अगस्त 1962 को हुआ था। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की और 1987 बैच के यूपी कैडर अधिकारी के रूप में सेवा शुरू की। अपने प्रशासनिक करियर के दौरान उन्होंने ललितपुर, आजमगढ़, बदायूं, अयोध्या, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर जिलों में जिलाधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दीं। उनके कार्यकाल के दौरान विशेष रूप से दिव्य के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गईं,



जिससे प्रदेश में इस क्षेत्र में सुधार और जागरूकता आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अवस्थी ने गृह सचिव, सूचना विभाग के प्रमुख और यूपी एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उनके प्रशासनिक नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और विकास कार्य पूरे हुए। इनमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रमुख हैं, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला उनकी देखरेख में रखी गई। उनके योगदान ने प्रदेश में यातायात और परिवहन के क्षेत्र में नई दिशा दी। इसके अलावा उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करने, पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण और तकनीकी सुधारों के कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद अवस्थी को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। पहले उनकी सेवाओं का विस्तार 2025-26 तक हुआ था। अब इस सेवा विस्तार के माध्यम से उनकी

भूमिका और भी प्रभावी हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में अवस्थी अपनी रणनीतिक और प्रशासनिक समझ का व्यापक उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें प्रदेश में प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव रखने का अवसर मिलेगा। उनके कार्यकाल के दौरान न केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक सुधारों में योगदान रहा, बल्कि प्रदेश में योजनाओं के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन में भी उनका योगदान सराहनीय रहा। अवनीश अवस्थी ने प्रदेश के विकास कार्यों में नवाचार और तकनीकी सुधारों को अपनाने की दिशा में कई पहल की हैं। उन्होंने प्रदेश में ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासनिक कार्यों को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों को सरकारी सेवाओं में आसान पहुंच मिली और कामकाज की पारदर्शिता बढ़ी। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि अवस्थी आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के

लिए रणनीतिक भूमिका निभा सकते हैं। उनके अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए उन्हें प्रदेश में पार्टी की नीतियों और विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रमुख जिम्मा दिया जा सकता है। अवनीश अवस्थी का सेवा विस्तार योगी सरकार के प्रशासनिक सुधारों और विकास कार्यों में निरंतर योगदान को मान्यता देता है। उनके अनुभव और कुशल नेतृत्व के कारण प्रदेश में योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में सुधार संभव हुआ है। आगामी वर्ष उनके प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव को और भी मजबूत करने वाला साबित होगा। अतः यह विस्तार न केवल उनके व्यक्तित्व और प्रशासनिक क्षमता को मान्यता देता है, बल्कि योगी सरकार के विकास और प्रशासनिक दृष्टिकोण में स्थिरता और प्रभावशीलता को भी दर्शाता है। अवनीश अवस्थी का योगदान उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था और विकास कार्यों के लिए लगातार प्रेरणास्पद रहेगा।

बनारस में शादी कम, तलाक के मामले ज्यादा

टीवी भारतवर्ष सीतापुर

बनारस में शादी के बाद तलाक और अलगाव के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 365 दिनों में शहर में कुल 1,500 शादियां हुईं, वहीं फैमिली कोर्ट में वैवाहिक विवाद के 2,250 मामले दाखिल हुए। यानी शादी कम, विवाद ज्यादा हो रहे हैं। औसतन हर महीने 188 और रोजाना लगभग छह मामले अलगाव के लिए अदालत में पहुंच रहे हैं। इनमें से 833 मामलों में कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। अधिवक्ता भरत सिंह का कहना है कि नवविवाहित जोड़ों के लिए शुरुआती तीन साल सबसे संवेदनशील होते हैं। इसी अवधि में अधिकतर तलाक और अलगाव के मामले सामने आते हैं। कई मामलों में तो शादी के कुछ महीनों के भीतर ही विवाद गहराकर अदालत तक पहुंच गए। चौंकाने वाली बात यह है कि 15 साल साथ रहने के बाद भी कई दंपती अलग होने के लिए मुकदमा दायर कर रहे हैं। फैमिली कोर्ट में ज्यादातर मामले तीन साल के अंदर की शादी के हैं। इन मामलों में खासकर 25-30 वर्ष की आयु वाले पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। अधिवक्ता सारिका दूबे ने बताया कि अधिकतर विवाद ऐसे जोड़ों में होते हैं जिन्होंने सच्चाई छिपाकर शादी की, जैसे नौकरी, पारिवारिक स्थिति या पहले के प्रेम संबंधों की जानकारी न देना। इसके अलावा देहेज प्रताड़ना, आर्थिक मांग, उत्पीड़न, एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर्स और नशे की लत जैसे कारण भी तलाक के मामलों में शामिल हैं। कुछ मामले नपुंसकता से संबंधित भी आते हैं। फैमिली कोर्ट में पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है और कई मामलों में सुलह कराई जाती है। हालांकि, बड़ी संख्या में जोड़े समझौते तक नहीं पहुंच पाते। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता की कमी, आर्थिक और व्यक्तिगत दबाव के कारण तलाक के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है।

आगरा में पेंशनर्स ने आठवें वेतन आयोग में भेदभाव के खिलाफ आंदोलन का ऐलान

टीवी भारतवर्ष आगरा

आगरा में बुधवार को संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के आह्वान पर कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार हॉल में पेंशनरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए आठवें वेतन आयोग में पुराने पेंशनरों को शामिल न किए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया और सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी गई। बैठक की अध्यक्षता अशोक कुमार कुलश्रेष्ठ सह संयोजक, आगरा ने की, जबकि संचालन वीर सिंह, जिला संयोजक, वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान ने संभाला। मुख्य वक्ता प्रांतीय सहसंयोजक शिव शंकर दुबे ने कहा कि सरकार ने चालाकी से आठवें वेतन आयोग के दायरे में केवल उन कर्मचारियों को रखा है जो 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त होंगे। 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त हुए लाखों पेंशनरों को इससे बाहर रखना अन्यायपूर्ण है। ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष आरके शर्मा ने कहा कि पेंशनर अपने हक के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।



उन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्यायालय से समाधान नहीं मिला तो पेंशनर अपनी वोट की ताकत से सरकार को झुकाने का काम करेंगे। पेंशनरों ने जोर देकर कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त रूप से आवाज उठाएंगे और अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। यह बैठक पुराने पेंशनरों के हक की रक्षा के लिए एक निर्णायक कदम के रूप में देखी जा रही है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ने की संभावना है।

मुरादाबाद में तेंदुए के घर में घुसने से मच गया हड़कंप

वन विभाग ने किया रेस्क्यू अभियान

टीवी भारतवर्ष मुरादाबाद

मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित हरथला गंगा मंदिर के पास बृहस्पतिवार को एक घर में तेंदुआ घुस गया, जिससे पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। घटना के दौरान मेघराज प्रजापति के परिवार ने तुरंत सुरक्षा उपाय किए और तेंदुए को बाथरूम में



बंद कर घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना ने मोहल्ले में अफरा-तफरी मचा दी। परिवार के अनुसार, सुबह घर के अंदर कुछ आवाज सुनाई दी। जांच करने पर बाथरूम में एक तेंदुआ बैठा हुआ पाया गया। परिवार ने तुरंत बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर शोर मचाना शुरू किया। इस पर आसपास के लोग तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने और जंगल में छोड़ने के लिए अभियान शुरू किया। टीम ने घर और आसपास के क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया ताकि तेंदुआ बाहर न निकल सके। स्थानीय पुलिस भी भीड़ को नियंत्रित करने में मदद कर रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए को बेहोश करके सुरक्षित जंगल में छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों को सलाह दी है कि वे अपने घरों में रहें और बच्चों को बाहर न भेजें। उन्होंने कहा कि तेंदुए के रिहायशी इलाके में आने से स्थानीय लोगों में डर व्याप्त है, लेकिन वन विभाग पूरी सतर्कता के साथ इसे नियंत्रित करने के प्रयास में जुटा हुआ है। इस घटना ने मुरादाबाद के रामगंगा विहार और आस-पास के इलाकों में लोगों की नींद उड़ा दी है और प्रशासन ने आपात स्थिति के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया है।

जहां उत्तर प्रदेश लाइन वहीं से

प्रति वर्ष 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन

गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में अग्रणी

करके दिखाए जो डबल इंजन सरकार है वो

UPGovtOfficial
 CMOUttarpradesh
 CMOfficeUP

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश